

an>

Title: Regarding non-payment of grant to poor people for construction of toilets under Swachh Bharat Abhiyan in Ajmer Parliamentary Constituency of Rajasthan.

डॉ. रघु शर्मा (अजमेर): धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के उन हजारों गरीब व्यक्तियों की समस्या की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अपने-अपने घरों में न चाहते हुए भी शौचालय बनाए।

आदरणीय अध्यक्ष जी, सरकार ने इसके लिए अधिकारियों को टारगेट दिया। उन गरीब आदमियों के पास दो जून की रोटी खाने को नहीं है, उन पर दबाव बना-बनाकर लक्ष्य की पूर्ति के लिए सरकारी अधिकारियों ने गरीबों से शौचालय बनवा लिए। इस बात को पूरा हिन्दुस्तान जानता है। यह एक तथ्यात्मक सच है। अगर सरकार वहां पानी की व्यवस्था करती, तो मैं समझता हूँ कि ये शौचालय बनाना आम आदमी की जिंदगी में लाभदायक होता। राजस्थान देश का भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन हमारे पास पानी सिर्फ एक परसेंट है। लोगों से यह कहा गया कि उनको भारत सरकार की तरफ से प्रति शौचालय बारह हजार रुपये मिलेंगे। उन लोगों ने कर्जा लेकर इन शौचालयों का निर्माण कर लिया। अब इन शौचालयों का निर्माण हुए दो बरस बीत गए हैं। महोदया, उन गरीबों के कर्जे पर ब्याज चालू हो गया है। पानी न होने की वजह से जो शौचालय बने, उनमें उन लोगों को पान, परचून की दुकान खोलनी पड़ गई।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस तरह के अभियान चलाने से पहले सरकार को देखना चाहिए कि किसी जगह की भौगोलिक परिस्थिति क्या है। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उन लाखों गरीब आदमियों को समय पर उनके पैसे का वितरण हो, ताकि वह गरीब आदमी ब्याज और कर्जे की मार से मुक्त हो सके। धन्यवाद।